



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 2017/अग्रहायण 20, 1939

No. 327] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 2017/AGRAHAYANA 20, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2017

प्रकरण सं. 05/2017

(मध्यवर्ती समीक्षा जांच पड़ताल)

विषय : यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम नाइट्रेट" के आयातों के संबंध में मध्यवर्ती समीक्षा जांच पड़ताल की शुरुआत।

फा. सं. 7/12/2017 – डी जी ए डी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित (जिसे इसके बाद नियमावली भी कहा जाएगा) सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं और पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के संबंध में;

पिछली जांच पड़ताल

मूल जांच पड़ताल

1. जबकि, उपर्युक्त अधिनियम और नियमावली के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा जाएगा) ने अधिसूचना सं. 54/1/2001 – डी जी ए डी दिनांक 02 नवंबर, 2001 के अनुसार यूरोपीय संघ और

ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्रेट (जिसे यहां इसके बाद संबद्ध वस्तु अथवा संबंधित उत्पाद भी कहा जाएगा) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच आरंभ की। प्रारंभिक जांच परिणामों को दिनांक 01 फरवरी, 2002 को अधिसूचित किया गया और इसे वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2002 की अधिसूचना सं. 34/2002-सीमा शुल्क के अनुसार लागू किया गया था। प्राधिकारी ने संबद्ध आयातों पर अंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए 28 अक्टूबर, 2002 को अंतिम जांच परिणाम को अधिसूचित किया। राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 132/2002- सीमा शुल्क दिनांक 29 नवंबर, 2002 के अनुसार दोनों नाम देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं पर अंतिम पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किए गए।

प्रथम निर्णायक समीक्षा

2. तत्पश्चात्, प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ (जिसे इसके बाद संबद्ध देश भी कहा गया है) से आयातों के संबंध में अधिसूचना संख्या 15/6/2005 – डी जी ए डी दिनांक 06 मार्च, 2007 के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांच पड़ताल आरंभ की। प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 15/6/2005 - डी जी ए डी दिनांक 03 मार्च, 2008 के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध आयातों, पर निश्चित पाटनरोधी शुल्कों के अधिरोपण को जारी रखने की सिफारिश की, और वित्त मंत्रालय ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर दिनांक 11 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना सं. 49/2008 – सीमा शुल्क के अनुसार निश्चित पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किया।

द्वितीय निर्णायक समीक्षा

3. तत्पश्चात् प्राधिकारी ने दिनांक 23 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. 15/1009/2012– डी जी ए डी के अनुसार द्वितीय निर्णायक समीक्षा आरंभ की। प्राधिकारी ने दिनांक 12 मई, 2014 की अधिसूचना सं. 15/1009/2012 – डी जी ए डी के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश की और वित्त मंत्रालय ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अधिसूचना सं. 37/2014-सीमा शुल्क, दिनांक 08 अगस्त, 2014 के अनुसार निश्चित पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किया।

अन्य संबंधित पाटनरोधी जांच पड़ताल

4. यूरोपीय संघ पर पाटनरोधी शुल्क के अतिरिक्त, वर्ष 2000 के बाद से चीन से आयातित संबद्ध वस्तुओं पर भी पाटनरोधी शुल्क लगता आ रहा है।

मध्यवर्ती समीक्षा को आरंभ करने के लिए अनुरोध

5. दीपक नाइट्रेट लिमिटेड ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क के अनुसरण में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्कों की समीक्षा आरंभ करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक एक हितबद्ध पक्षकार है क्योंकि यह भारत में समान वस्तु का उत्पादक है। याचिकाकर्ता भारतीय उत्पादन में प्रमुख समानुपात का समावेश रखता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वे परिस्थितियां, जो पिछली जांच की जांच अवधि के दौरान अभिभावी थीं, उनमें ऐसी स्थितियों के कारण उल्लेखनीय रूप से परिवर्तन हुआ है, जहां विद्यमान पाटनरोधी शुल्क प्रभावी नहीं रह गए हैं और प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में वृद्धि करने की जरूरत है।

समीक्षा के लिए आधार

6. याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि वर्तमान उपाय ऐसे पाटन को प्रभावहीन करने के लिए अपर्याप्त हैं जो क्षति का कारण है; पाटनरोधी शुल्क के प्रवृत्त होने के बावजूद पाटित कीमतों पर आयातों की महत्वपूर्ण मात्रा भारत में प्रवेश कर रही है; यह कि यूरोपीय संघ से वर्तमान आयात उल्लेखनीय पाटित कीमतों पर हो रहे हैं। याचिकाकर्ता ने आगे निवेदन किया है कि संबद्ध आयात पाटनरोधी शुल्क के वर्तमान स्तरों पर भी महत्वपूर्ण कीमत कटौती कर रहे हैं, वर्तमान क्षति मार्जिन प्रवृत्त वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की अपेक्षा महत्वपूर्ण रूप से उच्च है।

सामान्य मूल्य

7. आवेदक ने स्वीकार किया है कि संबद्ध देश के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की लागत और कीमतों के बारे में सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे। संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतों पर सार्वजनिक डोमेन में विश्वसनीय सूचना के अभाव में, संबद्ध देश में सामान्य मूल्य को पी ओ आई अवधि के लिए घरेलू उद्योग के, उत्पादन की लागत के आधार पर अनुमानित किया जाता है। अनुमान को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक उपायों और लाभों को शामिल करते हुए भली-भांति समायोजित किया गया है।

निर्यात कीमत

8. आवेदक ने डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देश से भारित औसत आयात कीमत के रूप में निर्यात कीमत के निर्धारण का दावा किया है। सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के लिए, व्यापार के समान स्तर पर दोनों की तुलना करना अनिवार्य है। निर्यात कीमतों को, सी आई एफ स्तर पर परिकलित किए जाने के कारण, उन्हें समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्ययों, अंतर्देशीय मालभाड़ा और बैंक प्रभारों के आधार के लिए समायोजित किया गया है।

पाटन मार्जिन

9. सामान्य मूल्य की कारखानागत निर्यात कीमत के साथ तुलना की गई है। इसके पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं कि संबद्ध देश में संबंध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखानागत निर्यात कीमत की तुलना में अधिक है, जो यह दर्शाता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुएं पाटित की जा रही हैं। पाटन मार्जिन उक्त न्यूनतम सीमा से अधिक होने का अनुमान है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

10. याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना घरेलू उद्योग पर क्षति के मूल्यांकन के लिए विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप कीमत कटौती और ह्रास, कीमत से कम कीमत पर बिक्री और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों की तुलना में कम लाभ, नियोजित पूंजी पर निम्न आय और माल सूची में गिरावट के रूप में परिणामी विपरीत प्रभावों के संबंध में प्रमाण उपलब्ध कराए हैं। बढ़ी हुई क्षतिरहित कीमत और घटी हुई उतराई कीमतों के परिणामस्वरूप क्षति मार्जिन में परिवर्तन हुआ है। इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि पिछली जांच की अवधि के दौरान अभिभावी परिस्थितियों में ऐसी स्थिति के कारण परिवर्तन हुआ है जहां वर्तमान पाटनरोधी मूल्य प्रभावी नहीं हैं और प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में वृद्धि किए जाने की जरूरत है।

(I) समीक्षा की शुरुआत

11. जबकि, उपर्युक्त नियमावली के संबंध में, प्राधिकारी को परिवर्तित परिस्थितियों के बारे में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहां वर्तमान पाटनरोधी शुल्क प्रभावी नहीं रहे हैं और यह कि प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क की मात्रा, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को बढ़ाए जाने की जरूरत है ताकि भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/1009/2012 – दिनांक 12 मई, 2014 और अधिसूचना सं. 46/2014 – सीमाशुल्क (ए डी डी) दिनांक 08 दिसंबर, 2014 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा लागू किए गए निश्चित शुल्क के अनुसार अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों की पाटनरोधी जांच पड़ताल की मध्यवर्ती समीक्षा आरंभ की जा सके और प्राधिकारी ने, एतद्वारा, बढ़े हुए स्तर पर पाटनरोधी वस्तुओं के सतत अधिरोपण की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए ऊपर दी गई नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9(क) के उपबंधों के अनुसरण में एक जांच आरंभ की है। समीक्षा में अधिसूचना सं. 15/1009/2012 – डी जी ए डी दिनांक 12 मई, 2014 के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

(ii) पी यू सी, समान वस्तु और उत्पाद वर्गीकरण

12. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, अपने सभी रूपों में "सोडियम नाइट्रेट" है जैसा कि यह तृतीय निर्णायक समीक्षा जांच सहित पिछली जांचों में था। यह एक मध्यवर्ती समीक्षा होने के कारण, वर्तमान जांच पिछली जांच में शामिल उत्पाद को शामिल करती है।
13. सोडियम नाइट्रेट एक अकार्बनिक रसायन है और ऑक्सीकरण करने और कम होने वाला एजेंट है। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय पाउडर है जो अधिकतर फर्मास्युटिकल उद्योगों, रंगाई उद्योगों, लुब्रीकेंट्स, निर्माण रसायनों, रबड़ ब्लॉइंग एजेंटों, हीट ट्रांसफर साल्ट्स, मांस प्रसंस्करण, वस्त्र निर्माण आदि में प्रयुक्त किया जाता है।
14. उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमा शुल्क शीर्ष 28.34.10 के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
15. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन; मूल्य विनिर्देशन, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं को वर्गीकरण के रूप में समान उत्पाद है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्ता दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" के रूप में मानते हैं।

(iii) शामिल देश

16. वर्तमान जांच यूरोपीय संघ से आयातों पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क पर एक मध्यवर्ती समीक्षा होने के कारण वर्तमान जांच में शामिल देश केवल यूरोपीय संघ हैं जिसे "संबद्ध देश" कहा गया है।

(iv) प्रस्तावित जांच की अवधि (पी ओ आई)

17. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अक्टूबर, 2016 से सितंबर, 2017 (12 महीने) है। तथापि, क्षति जांच अवधि में 2014-15, 2015-16, 2016-17 और पी ओ आई (जांच की अवधि) शामिल होंगे।

(v) सूचना प्रस्तुत करना

18. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक और निर्यातक, भारत के उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद के साथ संबद्ध भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में व निर्धारित तरीके से प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत कर सकें और अपने विचार नीचे दिए गए पते पर प्राधिकारी को भेज सकें :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110 001.

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई सूचना नीचे दे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से निर्धारित प्रपत्र में (जो प्राधिकारी की वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) से डालनलोड किया जा सकता है) भेज सकता है।

(vi) समय सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई जानकारी और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए ताकि वह अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से अधिक ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी तक पहुंच सके। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर अपने परिणाम दर्ज करा सकते हैं।
21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे तत्कालीन मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और अपनी प्रश्नावली के प्रत्युत्तरों को और पाटनरोधी उपायों को लागू करने की आवश्यकता के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन के संबंध में अपनी टिप्पणियों को इस जांच के आरंभ होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर दायर करें।

(vii) गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. यदि प्रश्नावली के प्रत्युत्तर/ प्रस्तुतियों के किसी भाग पर गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे पृथक दो सैटों में प्रस्तुत करना होगा (क) गोपनीयता के रूप में चिह्नित (शीर्षक सूची, पृष्ठों की संख्या आदि सहित) और (ख) अगोपनीय के रूप में चिह्नित अन्य सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठों की संख्या आदि सहित)। प्रस्तुत की गई सारी जानकारी के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी भाग पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।
23. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत करानी होंगी।
24. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचनाप्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/ अथवा ऐसी सूचना का सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिनके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/ रिक्त छोड़ी गई है और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने की अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
27. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में उचित कारण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद, प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकारों के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

(viii) सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

28. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

(ix) असहयोग

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यकता सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

New Delhi, the 11th December, 2017

INITIATION NOTIFICATION

Case No. 05/2017

(Mid-Term Review Investigation)

Subject: Initiation of Mid-Term Review investigation concerning imports of “Sodium Nitrite” originating in or exported from European Union.

F. No. 7/12/2017- DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

Previous Investigations**The original investigation**

1. Whereas, having regard to the above Act and the Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) initiated an anti-dumping investigation concerning imports of Sodium Nitrite (hereinafter also referred to as the subject goods or product concerned) originating in or exported from European Union and Taiwan, vide Notification No. 54/1/2001-DGAD dated November 02, 2001. The Preliminary Findings were notified on February 01, 2002 and the same were imposed by Ministry of Finance vide Notification No. 34/2002-Customs dated March 28, 2002. The Authority notified final findings on October 28, 2002 recommending definitive antidumping duty on the subject imports. The definitive anti dumping duties on the subject goods imported from both the name countries were imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 132/2002-Customs dated November 29, 2002.

The First Sunset Review

2. Subsequently, the Authority initiated sunset review investigations vide Notification No. 15/6/2005—DGAD dated March 06, 2007 concerning imports from European Union (hereinafter also referred to as subject country). The Authority recommended continued imposition of definitive anti dumping duties on the subject imports from the subject country vide notification No.15/6/2005-DGAD, dated March 03, 2008 and Ministry of Finance extended definitive anti-dumping duty vide notification No.49/2008- Customs, dated the April 11, 2008 on all imports of the subject goods from the subject country.

The Second Sunset Review

3. Subsequently, the Authority initiated second sunset review investigations vide Notification No. 15/1009/2012- DGAD dated March 23, 2013. The Authority recommended continued imposition of definitive anti dumping duties on the subject imports from the subject country vide Notification No. 15/1009/2012- DGAD, dated May 12, 2014 and Ministry of Finance extended definitive anti-dumping duty vide notification No.37/2014- Customs, dated August 08, 2014 on imports of the subject goods from the subject country.

The other related Anti-Dumping Investigation

4. In addition to the anti-dumping duty on European Union, the subject goods imported from China are also attracting anti-dumping duty since the year 2000.

Request for initiation of Mid-Term Review

5. Deepak Nitrite Limited has submitted an application requesting for initiation of a review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods from the subject country in accordance with section 9A of the Customs Tariff Act 1975 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. The applicant is an interested party as it is a producer of the like article in India. The applicant commands a major proportion in Indian production. The applicant has claimed that the circumstances that were prevalent during the period of investigation of the previous investigation have changed significantly leading to a situation where the existing anti-dumping duties are no longer effective and that there is need of enhancement of quantum of the anti-dumping duty in force.

Grounds for Review

6. The Applicant has submitted that the existing measures are insufficient to counteract the dumping which is causing injury; that significant volume of imports at dumped prices are entering India in spite of anti-dumping duty being in force; that the current imports from European Union are at significant dumped prices. The applicant has further submitted that the subject imports are causing significant price undercutting even at the existing levels of antidumping duty, the current injury margin is substantially higher than the current anti dumping duty in force.

Normal Value

7. The applicant has submitted that efforts were made to get information/evidence about cost and prices of subject goods in the domestic market of the subject country. In the absence of availability of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject country, the Normal value in the subject country has been estimated on the basis of cost of production of the domestic industry for POI period. The estimation has been duly adjusted including selling, general and administrative expenses and profit.

Export Price

8. The applicant has claimed determination of export price as the average import price from subject country on the basis of data procured from DGCI&S. For fair comparison between the normal value and export price, it is necessary to compare the two at the same level of trade. The export prices being calculated at the CIF level, have been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight and bank charges.

Dumping Margin

9. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the ex-factory export price, indicating that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margin is estimated to be above de-minimis.

Injury and Causal Link

10. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms, price undercutting and depression, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of less profit as compared to the exports done by the applicant, low return on

capital employed and piled up inventories. The injury margin has undergone change as a result of increased non-injurious price and decreased landed price. There is sufficient prima facie evidence that the circumstances that were prevalent during the period of investigation of the previous investigation have changed significantly leading to a situation where the existing anti-dumping duties are no longer effective and that there is need for enhancement of quantum of the anti-dumping duty in force.

(i) Initiation of the Review

11. Whereas, having regard to the above Rules, the Authority finds sufficient prima facie evidence of changed circumstances leading to a situation where the existing anti-dumping duties are no longer effective and that there is need of enhancement of quantum of the anti-dumping duty in force; enhanced injury margin; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury, to initiate a mid-term review anti-dumping investigation of the final findings notified vide Notification No. 15/1009/2012- dated May 12, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I and the definitive duties imposed by the Central Government vide Notification No.46/2014 Customs (ADD) dated December 08, 2014 and the Authority hereby initiates an investigation in accordance with the provisions of Section 9(A) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 of the Rules supra to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties at enhanced level. The review will cover all aspects of Notification No. 15/1009/2012 DGAD dated May 12, 2014.

(ii) PUC, Like Articles and Product Classification

12. The product under consideration in the present investigation is "Sodium Nitrite" in all its forms as it was in the previous investigations including the third sunset review investigation. This being a mid-term review, the present investigation covers the product covered in the previous investigation.
13. Sodium Nitrite is an inorganic chemical and is oxidizing and reducing agent. It is a white crystalline powder mostly used in pharmaceuticals industries, dye industries, lubricants, construction chemicals, rubber blowing agent, heat transfer salts, meat processing, textiles etc.
14. The product is classified under Customs Tariff heading 28.34.10 of the Customs Tariff Act. This classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
15. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are like article to the imported product in terms of parameters such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The applicant has claimed that subject goods produced by them and the subject goods imported from the subject country are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicant in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

(iii) Country/ies involved

16. The present investigation being a mid-term review on existing anti-dumping duty on imports from European Union, the country involved in the present investigation is European Union only (referred to as the "subject country").

(iv) Proposed POI

17. The period of investigation for the purpose of the present review is Oct., 2016 to Sep., 2017 (12 months). The injury investigation period will however cover the periods 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the POI.

(v) Submission of Information

18. The known producers and exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,

4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street, New Delhi -110001.

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form (downloadable from the website of the Authority at (www.dgtr.gov.in) and manner prescribed within the time limit set out below.

(vi) Time Limit

20. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.
21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

(vii) Submission of information on confidential basis

22. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
23. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non- confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
24. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional

circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

(viii) Inspection of public file

28. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non- confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

(ix) Non-cooperation

29. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority